GEO IAS
It's about quality

5 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET

Date: 5 July 2024

Important News Articles

1. जयशंकर ने वांग यी से मुलाकात में कहा कि LAC का सम्मान किया जाना चाहिए – द हिंदू
2. मेघालय ने भी आयुष्मान केंद्रों के लिए 'मंदिर' टैग को अस्वीकार किया - द हिंदू
3. केंद्र ने परीक्षण के वित्तपोषण के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए – पीआईबी
4. क्वाड अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक; प्रतिबद्धता को रेखांकित किया
5. 'प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लीक होने की रोकथाम में राज्यों मदद की जरूरत - केंद्र - इंडियन एक्सप्रेस
6. सरकार ने जलवायु-अनुकूल खेती हेतु योजना तैयार की – इंडियन एक्सप्रेस
7. प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन भारत मंडपम में शुरू हुआ – पीआईबी
8. इनपुट लागत को शामिल करने हेतु उत्पादक मूल्य सूचकांक का नया मॉडल - इंडियन एक्सप्रेस

Editorials, Gists and Explainers

9. क्या भारत को मानवीय संकट के मद्देनजर अपनी म्यांमार नीति की समीक्षा करनी चाहिए? – द हिंदू
10. भारत के लिए पांच वर्षीय जलवायु एजेंडे का स्वरूप - द हिंदू

Quick Look

1. भारत में घड़ियाल की आबादी - द हिन्दू
2. रेडिएशन बायोडोसिमेट्री – द हिंदू
3. स्वामी विवेकानंद – पीआईबी

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. जयशंकर ने वांग यी से मुलाकात में कहा कि LAC का सम्मान किया जाना चाहिए – द हिंदू

प्रासंगिकता:
जीएस II – भारत और उसके पड़ोसी संबंध

प्रीलिम्स टेकअवे
- LAC

प्रसंग:
- अप्रैल-मई 2020 से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को पार कर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।
- भारत सरकार चीन के मुद्दे को संबोधित करने में सतर्क रही है।

चर्चा में क्यों?
- 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई।
- अब सैन्य कमांडरों द्वारा सैनिकों की वापसी के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) क्या है?
- यह भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- तीन क्षेत्रों में विभाजित: पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम), मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और पश्चिमी (लद्दाख)।
- भारत का दावा है कि LAC 3,488 किमी लंबी है; चीन लगभग 2,000 किमी का दावा करता है।
- भारत की आधिकारिक सीमा (सर्वे ऑफ इंडिया) में अक्साई चिन और गिलगित-बाल्टिस्तान शामिल हैं।

LAC बनाम पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC):
- नियंत्रण रेखा पर 1948 के बाद युद्ध विराम स्थापित हुआ, जिसे शिमला समझौते के तहत 1972 में औपचारिक रूप दिया गया।
- LoC के विपरीत LAC को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता या सीमांकन नहीं किया गया है।

LAC पर असहमति:
- पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख मतभेद, 1959 में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे गए पत्रों से उत्पन्न हुए।
- 1962 के युद्ध के बाद भारत ने चीन के 1959 और 1962 के LAC दावों को खारिज कर दिया।
- डोकलाम संकट (2017) ने चीन के "1959 LAC" के दावे को उजागर किया।

लद्दाख में विवाद:
- अक्साई चिन ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था; पश्चिमी लद्दाख में सीमा अनिर्धारित थी।

वर्तमान व्यवस्था:
- भारत ने 1993 में LAC को वैचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- संयुक्त कार्य समूह को LAC संरेखण को स्पष्ट करने का कार्य सौंपा गया।

पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने की योजना:
- 2020 से चर्चा के तहत सैन्य वापसी और विघटन चरणों का विवरण।
- कोर कमांडरों के बीच वार्ता के परिणामस्वरूप सीमित संख्या में सैनिकों को पीछे हटाया गया तथा बफर जोन का निर्माण किया गया।

विरासत संबंधी मुद्दे:
- देपसांग मैदान और डेमचोक मुद्दे 2020 की घुसपैठ से पहले के हैं।
- दौलत बेग ओल्डी के पास देपसांग मैदानों (2013) में PLA की घुसपैठ का मामला अभी तक सुलझा नहीं है।
- चारडिंगनिंगलुंग नाला (CNN) जंक्शन पर डेमचोक मुद्दे जारी हैं।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

2. मेघालय ने भी आयुष्मान केंद्रों के लिए 'मंदिर' टैग को अस्वीकार किया - द हिंदू

प्रासंगिकता:
जीएस II – स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

प्रीलिम्स टेकअवे
- ABHA

प्रसंग:
- मिजोरम और नागालैंड के साथ मेघालय ने भी अपने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने से इनकार कर दिया है।
- धार्मिक जनसांख्यिकी को देखते हुए यह इनकार उल्लेखनीय है: मेघालय की लगभग 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि मिजोरम और नागालैंड में यह संख्या 90% है।

ABHA क्या है?
- ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) एक अद्वितीय 14-अंकीय संख्या है जो व्यक्तियों को उनके सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए दी जाती है, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) में नामांकन निःशुल्क है, जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य आईडी या ABHA बना सकते हैं।

विशेषताएँ:
- इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR): ABHA EHR को एकीकृत करता है, जिससे रोगी की जानकारी का कुशल भंडारण और पुनर्प्राप्ति संभव होती है, जिससे चिकित्सा इतिहास बनाए रखा जा सकता है और स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- पोर्टेबिलिटी: ये खाते आयुष्मान भारत योजना के तहत विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच पोर्टेबल हैं, जिससे लाभार्थियों को विभिन्न स्थानों पर सेवाओं तक निर्बाध पहुंच की सुविधा मिलती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: लेन-देन को डिजिटल बनाकर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखकर, ABHA स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है।

आयुष्मान भारत योजना क्या है?
- आयुष्मान भारत योजना: जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रमुख योजना को सितंबर 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के बाद लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) हासिल करना है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इस मिशन का उद्देश्य भारत के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक रीढ़ विकसित करना है, डिजिटल राजमार्गों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर को पाटना है।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हालिया सरकारी पहल:
- **स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र:** फरवरी 2018 में घोषित ये केंद्र मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (HWC) में बदल देते हैं। ये HWC आयुष्मान भारत की नींव हैं, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन, निःशुल्क आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करते हैं।
- **जन औषधि केंद्र:** ये केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हों।
- **ई-संजीवनी:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की यह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रलेखित टेलीमेडिसिन कार्यान्वयन बन गई है, जो ग्रामीण और दूरदराज के समुदायों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

3. केंद्र ने परीक्षण के वित्तपोषण के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए – पीआईबी

प्रासंगिकता:
जीएस II – सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

प्रसंग:
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत सहायता के वित्तपोषण के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश मिशन की सफलता के लिए आवश्यक मानकों और नियामक ढांचे को विकसित करने पर केंद्रित हैं।

- नये दिशानिर्देश हरित हाइड्रोजन घटकों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए वर्तमान परीक्षण सुविधाओं में अंतराल की पहचान करने में मदद करेंगे।
- इससे नई परीक्षण सुविधाओं के निर्माण में सुविधा होगी तथा सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹200 करोड़ के कुल बजट वाली यह योजना, मिशन के तहत व्यापक ₹19,744 करोड़ आवंटन का हिस्सा है।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है?

- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि भारत को इस ईंधन के शुद्ध निर्यातक के रूप में स्थापित किया जा सके।
- मिशन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन की मांग सृजन, उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देना है।

उपयोजनाएँ:

- **हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT):** इस पहल से इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को वित्तपोषित किया जाएगा।
- **हरित हाइड्रोजन केन्द्र:** हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन या उपयोग की क्षमता वाले राज्यों और क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना।
- 2030 तक लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना।
- इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने और लगभग छह लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।
- इससे जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आएगी तथा वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी।

महत्व:

- यह मिशन औद्योगिक, गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में योगदान देगा।
- इसका उद्देश्य आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता कम करना है।
- इससे स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- यह मिशन कुशल ईंधन कोशिकाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

संभावना:

- भारत में अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां तथा प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और पवन संसाधन हैं, जो इसे हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आदर्श बनाते हैं।
- हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियां उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हैं जहां प्रत्यक्ष विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण है, जैसे भारी-भरकम, लंबी दूरी के परिवहन, कुछ औद्योगिक क्षेत्र और दीर्घकालिक विद्युत भंडारण।
- उद्योग का प्रारंभिक चरण क्षेत्रीय केन्द्रों के निर्माण का अवसर प्रस्तुत करता है जो उच्च मूल्य वाले हरित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँ:

- **विश्व स्तर पर नवजात अवस्था:** दुनिया भर में हरित हाइड्रोजन का विकास अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। जबकि भारत एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभर सकता है, वर्तमान में सभी मध्यवर्ती चरणों का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है।
- **आर्थिक स्थिरता:** एक महत्वपूर्ण चुनौती हरित हाइड्रोजन उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता है। हाइड्रोजन को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, इसे पारंपरिक ईंधन और प्रौद्योगिकियों के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी होना चाहिए।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है जिसका उपयोग अमोनिया, इस्पात, शोधन प्रक्रियाओं और बिजली के उत्पादन में किया जाता है।
- वर्तमान में, अधिकांश हाइड्रोजन कोयले से प्राप्त होता है और इसे 'काला' या 'भूरा' हाइड्रोजन कहा जाता है।

- शुद्ध हाइड्रोजन दुर्लभ है; यह आमतौर पर H2O (पानी) जैसे यौगिकों में मौजूद होता है। नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस, पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर सकता है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है।
- विभिन्न रंग हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्युत स्रोत को इंगित करते हैं, जैसे भूरा (कोयला), ग्रे, नीला और हरा (नवीकरणीय स्रोत)।

मौजूदा उत्पादन:

- उच्च लागत के कारण, वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन में हरित हाइड्रोजन का योगदान 1% से भी कम है।
- उत्पादन लागत अलग-अलग होती है: ब्लैक हाइड्रोजन (USD 0.9-1.5/kg), ग्रे हाइड्रोजन (USD 1.7-2.3/kg), ब्लू हाइड्रोजन (USD 1.3-3.6/kg), और ग्रीन हाइड्रोजन (USD 3.5-5.5/kg)।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन की आवश्यकता:

- हाइड्रोजन में प्रति इकाई भार में उच्च ऊर्जा सामग्री होती है, जो इसे रॉकेट ईंधन के लिए भी एक मूल्यवान ऊर्जा स्रोत बनाती है।
- ग्रीन हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक है, जिसमें लगभग शून्य उत्सर्जन होता है। यह कारों में ईंधन कोशिकाओं और उर्वरक और इस्पात निर्माण जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए उपयुक्त है।
- हरित हाइड्रोजन क्षमता निर्माण के वैश्विक प्रयासों का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पहल:

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- पीएम-कुसुम
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
- छत पर सौर ऊर्जा योजना

आगे की राह:

- औद्योगिक हाइड्रोजन उपयोगकर्ताओं को हरित हाइड्रोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- पाइपलाइनों, टैंकरों, भंडारण और वितरण नेटवर्क सहित आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना महत्वपूर्ण है।
- हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम आवश्यक है।
- कम लागत वाले नवीकरणीय संयंत्रों का लाभ उठाने तथा सौर और पवन नीलामी से लागत में कटौती के अनुभव से हरित हाइड्रोजन की लागत को कम किया जा सकता है।
- भारत की युवा जनसांख्यिकी और संपन्न अर्थव्यवस्था हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण बाजार संभावनाएं प्रस्तुत करती है।

4. क्वाड अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक; प्रतिबद्धता को रेखांकित किया

प्रासंगिकता:

जीएस II – अंतर्राष्ट्रीय समूह

प्रीलिम्स टेकअवे

- मालाबार अभ्यास

प्रसंग:

- विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मई 2023 में समूह के शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में विभिन्न क्वाड कार्य समूहों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की है।

क्वाड का परिचय

- क्वाड सुरक्षा वार्ता, जिसे आमतौर पर क्वाड के नाम से जाना जाता है, में चार लोकतांत्रिक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं।
- 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रस्ताव से उत्पन्न क्वाड का उद्देश्य एक स्थिर, खुला और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
- औपचारिक रूप से 2017 में स्थापित क्वाड के मुख्य उद्देश्यों में स्वतंत्र एवं निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखना शामिल है।

हालिया घटनाक्रम और समीक्षा

- हाल ही में क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मई 2023 शिखर सम्मेलन के बाद गठित विभिन्न कार्य समूहों की प्रगति का आकलन किया।
- विदेश मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला तथा समुद्री सुरक्षा और आर्थिक उन्नति में सहयोग पर बल दिया।
- क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के लिए सामरिक अवसर है

चीन के प्रभाव का प्रतिकार

- क्वाड भारत को चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में।
- हिंद महासागर चीनी व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में समुद्री सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।
- क्वाड साझेदारों के साथ सहयोग के माध्यम से भारत संभावित रूप से चीनी व्यापार मार्गों को बाधित कर सकता है, जिससे उसका क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ सकता है।

नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरना

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के केन्द्र में स्थित भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी गतिविधियां भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत कर सकती हैं।
- क्वाड राष्ट्रों के साथ गठबंधन करके भारत का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, साम्राज्यवादी नीतियों का मुकाबला करना और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

चुनौतियाँ और मुद्दे

अनिर्धारित रणनीतिक दृष्टि

- अपनी क्षमता के बावजूद, क्वाड को स्पष्ट रूप से परिभाषित रणनीतिक मिशन के अभाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से समूह की समावेशिता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से परे इसके दायरे पर सवाल उठते हैं।

गठबंधन प्रणालियों के प्रति भारत की अनिच्छा

- औपचारिक गठबंधन प्रणालियों के प्रति भारत का ऐतिहासिक विरोध, क्वाड की रणनीतिक भागीदारी को गहरा करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- यह रुख अन्य क्वाड सदस्यों के अधिक एकीकृत सुरक्षा दृष्टिकोण के विपरीत है, जो समूह की एकजुटता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।
- भविष्य की दिशाएँ और सिफारिशें

हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को स्पष्ट करना

- क्वाड राष्ट्रों को एक व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जो आर्थिक हितों को सुरक्षा अनिवार्यताओं के साथ संरेखित करे।
- उद्देश्यों को स्पष्ट करने और पारदर्शिता बढ़ाने से क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के रूप में क्वाड की विश्वसनीयता बढ़ सकती है।

विस्तार और समावेशिता

- भारत क्वाड की सदस्यता का विस्तार कर इसमें इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे प्रमुख हिंद-प्रशांत हितधारकों को शामिल करने की वकालत करता है।
- साझेदारी का विस्तार करके, क्वाड क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

- क्वाड भारत और उसके साझेदारों के लिए क्षेत्रीय हितों की रक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।
- क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में क्वाड की क्षमता को साकार करने के लिए रणनीतिक चुनौतियों का समाधान करना और सहयोगात्मक प्रयासों का विस्तार करना आवश्यक होगा।

5. 'प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लीक होने की रोकथाम में राज्यों मदद की जरूरत - केंद्र - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- NTA

समाचार: केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से मदद मांगी है।

मुख्य बिंदु:
- गृह सचिव ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की और आगामी परीक्षाओं के संचालन की निगरानी में उनकी सहायता मांगी।
- बैठक के दौरान गृह सचिव ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने राज्यों में प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक सिविल और एक पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त करके परीक्षाओं पर निगरानी का एक अतिरिक्त स्तर स्थापित करने में मदद करें।
  - पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि परीक्षा निष्पक्ष हो तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से मुक्त हो।
- इसके अतिरिक्त, राज्यों को परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के साथ समन्वय करने के लिए एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया।
- वर्तमान में, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।
- हालांकि, NEET-UG पेपर के कथित लीक से संबंधित कई गिरफ्तारियों सहित कई केंद्रीय रूप से आयोजित प्रवेश परीक्षाओं की अखंडता पर विवाद ने सरकार को सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपनी प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया है।
- इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के अलावा मूल मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा।

सामान्य अध्ययन III

6. सरकार ने जलवायु-अनुकूल खेती हेतु योजना तैयार की – इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता:
जीएस III – भारतीय कृषि

प्रीलिम्स टेकअवे
- कृषि से संबंधित योजनाएं और तकनीकें खबरों में

प्रसंग:
- केंद्र सरकार जलवायु के लिहाज से संवेदनशील जिलों में स्थित 50,000 गांवों में जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा पेश करने की तैयारी कर रही है। यह पहल जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में शुरू करने के लिए तैयार है। एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही इस कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।

भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव:
- **वर्षा पैटर्न में परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिससे वर्षा का समय, तीव्रता और वितरण प्रभावित हुआ है।
  - इन परिवर्तनों के कारण सूखा, बाढ़ और अनियमित वर्षा हो सकती है, जिसका कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए, 2019 में देरी और कम मानसूनी बारिश के कारण भारत के कई क्षेत्रों में फसल की पैदावार कम हो गई।
- **तापमान में वृद्धि:**
  - बढ़ते तापमान से फसल की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- बढ़ते मौसम के दौरान उच्च तापमान से फसल की पैदावार कम हो सकती है और फसलों का पोषण मूल्य कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, गर्मी का तनाव पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकता है।
- भारत में हाल की गर्म लहरों ने विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसी गर्मी के प्रति संवेदनशील फसलों को प्रभावित किया है, जिससे उनकी पैदावार कम हो गई है।

- **कीट एवं रोग पैटर्न में परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन कीटों और बीमारियों के वितरण और प्रचुरता को बदल देता है, जिससे कृषि कीट प्रबंधन जटिल हो जाता है।
  - तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन से कुछ कीटों और बीमारियों के फैलने को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे फसल के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिए, गुलाबी बॉलवर्म जैसे कीटों के बढ़ते प्रकोप ने भारत में कपास उत्पादन को नुकसान पहुंचाया है, तथा अनियमित वर्षा के कारण सोमालिया क्षेत्र से आए टिड्डियों के झुंड ने भी बड़ी चुनौतियां उत्पन्न की हैं।
- **पानी की कमी:**
  - जलवायु परिवर्तन जल उपलब्धता को प्रभावित करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो सिंचाई के लिए वर्षा या बर्फ पिघलने पर निर्भर हैं।
  - वर्षा के बदलते पैटर्न और पिघलते ग्लेशियरों के कारण जल की कमी हो सकती है, विशेष रूप से फसल वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो सकती है और जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
- **फसल पद्धति में परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की उपयुक्तता को प्रभावित करता है, जिससे उत्पादकता बनाए रखने के लिए फसल पैटर्न में समायोजन आवश्यक हो जाता है।
  - कुछ फसलें कम व्यवहार्य हो सकती हैं, जबकि अन्य अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर, जलवायु परिवर्तन से नारियल उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है।
- **चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि:**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात, तूफान और ओलावृष्टि जैसी चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे फसलों, पशुधन और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे उपज में हानि हुई है और किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
  - इसका एक हालिया उदाहरण चक्रवात बिपोरजॉय है।

आगे राह

- **इनपुट-गहन से ज्ञान-गहन कृषि तक:**
  - भारत की विविध कृषि पद्धतियों के कारण भविष्य के लिए उपयुक्त समाधानों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय संवाद में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना आवश्यक हो गया है।
  - उन्नत विश्व सटीक पद्धतियों और इनपुट अनुप्रयोग के लिए सेंसर और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए सटीक खेती की ओर बढ़ रहा है।
  - भारत में उच्च तकनीक, सटीक कृषि पद्धतियों को अपनाने से औसत लागत कम हो सकती है, किसानों की आय बढ़ सकती है, तथा पैमाने से संबंधित कई चुनौतियों का समाधान हो सकता है।
- **अंतर फसल और कृषि वानिकी:**
  - एक ही खेत में विभिन्न फसलों को एक साथ उगाने या फसलों के साथ पेड़ लगाने से जैव विविधता बढ़ सकती है, मृदा अपरदन कम हो सकता है, तथा जलवायु लचीलापन बढ़ सकता है।
  - अनाज के साथ फलियों की अंदर फसलीय खेती न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती है, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार करती है।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली गैर-पारंपरिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने से एक ही फसल पर निर्भरता कम हो सकती है और जोखिम कम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूखा-सहिष्णु बाजरा को बढ़ावा देने से किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में मदद मिल सकती है।
- **जलवायु-स्मार्ट जल प्रबंधन:**
  - कृषि में जलवायु लचीलापन प्राप्त करने के लिए कुशल जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में।

- जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन पद्धतियों के क्रियान्वयन से जल संसाधनों का संरक्षण करते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
- वर्षा जल को संग्रहित करने और संग्रहीत करने के लिए तालाब, चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण करने से भूजल को पुन:पूरण करने और सूखे के दौरान सिंचाई प्रदान करने में मदद मिल सकती है। किसान सूखे के दौरान या पूरक सिंचाई के लिए इस संग्रहित पानी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अनियमित वर्षा पैटर्न पर निर्भरता कम हो जाती है।

7. प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन भारत मंडपम में शुरू हुआ – पीआईबी

प्रासंगिकता:
जीएस III – पर्यावरण संरक्षण

प्रीलिम्स टेकअवे
• SWM नियम 2016
• प्रदूषण

प्रसंग:

- प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन (GCPRS) प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, सचिव, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और मुख्य अतिथि श्रीमती मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शामिल थे। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में उद्योग जगत के नेता जैसे श्री मनीष देधिया (AIPMA अध्यक्ष), श्री कमल नानावटी (CPMA अध्यक्ष) और संबंधित क्षेत्रों के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे।

प्लास्टिक प्रदूषण के सामान्य स्रोत:

- व्यापारिक जहाज प्लास्टिक आधारित माल, सीवेज और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न अपशिष्टों को महासागर में छोड़ते हैं।
- मछली पकड़ने के बेकार उपकरण प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा महासागरीय स्रोत हैं।
- महाद्वीपीय प्लास्टिक कचरा, जैसे कि खाद्य रैपर, कंटेनर, बोतलें और बैग, मुख्य रूप से तूफानी जल अपवाह के माध्यम से महासागरों में प्रवेश करते हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट की सीमा:

- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - 1950 से अब तक 3 बिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 60% लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में समाप्त हो जाता है।
  - केवल 9% का पुनर्चक्रण किया जाता है, 12% को जला दिया जाता है, तथा शेष लैंडफिल या पर्यावरण में जमा हो जाता है।
- **भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट:**
  - भारत में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक उत्पन्न होता है, जिसमें से 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्रित नहीं किया जाता।
  - प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के 2020 तक प्रतिवर्ष 22 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा एकल-उपयोग प्लास्टिक का होगा।
  - भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 11 किलोग्राम से भी कम है, जो कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

प्लास्टिक कचरे का प्रभाव:

- **आर्थिक नुकसान:** प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यटन राजस्व को प्रभावित करता है, विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में।
- **जानवरों के लिए निहितार्थ:** समुद्री जीवन को अंतर्ग्रहण और उलझाव के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिससे मृत्यु दर और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होता है।
- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** प्लास्टिक से निकलने वाले रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करते हैं और संभावित रूप से आनुवंशिक विकार पैदा करते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** प्लास्टिक कचरे से होने वाला भूमि, वायु और जल प्रदूषण आवासों, जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, तथा आक्रामक प्रजातियों के परिवहन में योगदान देता है।

चुनौतियाँ:

- **प्लास्टिक अपशिष्ट का कुप्रबंधन:** अपर्याप्त प्रबंधन से व्यापक प्रदूषण होता है, जिसमें समुद्री कचरा पैचों का निर्माण भी शामिल है।
- **नकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक:** कठोर परीक्षण के अभाव में नकली बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बाजार में प्रवेश कर जाते हैं।
- **ई-कॉमर्स का प्रभाव:** ऑनलाइन खुदरा और खाद्य वितरण सेवाएं शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को बढ़ाने में योगदान देती हैं।

समाधान: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- **कटौती:** प्लास्टिक बैग पर कर जैसी नीतियों का समर्थन करें और विनिर्माण पर रोक लगाएं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे विकल्पों को बढ़ावा दें।
- **पुन: उपयोग:** नए उत्पादों की मांग को कम करने के लिए प्लास्टिक के पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करें।
- **पुनर्चक्रण:** आर्थिक लाभ उत्पन्न करने, रोजगार सृजित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्लास्टिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष:

- प्लास्टिक कचरे का प्रभावी प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने और रीसाइक्लिंग पहल को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता संधारणीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

8. इनपुट लागत को शामिल करने हेतु उत्पादक मूल्य सूचकांक का नया मॉडल - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, विकास, प्रगति और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- PPI
- WPI

समाचार: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के एक नए मॉडल को अंतिम रूप दिया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ साझा किया है।

मुख्य बिंदु:

- यह नया मॉडल अर्थव्यवस्था में इनपुट कीमतों को कुशलतापूर्वक पकड़ने के लिए है
  - अधिकांश G20 अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप सरकार धीरे-धीरे WPI से PPI की ओर बढ़ रही है।
- सरकार 2011-12 से थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को बदलने की दिशा में भी काम कर रही है
  - DPIIT ने 2021 में एक कार्य समूह की मसौदा तकनीकी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने का सुझाव दिया गया था।
- इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ परामर्श किया गया है

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. क्या भारत को मानवीय संकट के मद्देनजर अपनी म्यांमार नीति की समीक्षा करनी चाहिए? – द हिंदू

प्रासंगिकता:

जीएस II - भारत और उसके पड़ोसी, द्विपक्षीय समूह और समझौते

प्रसंग:

- **जातीय सशस्त्र संगठनों (EAO)** और **सैन्य जुंटा** के बीच चल रहे संघर्ष ने गंभीर मानवीय संकट को जन्म दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर चर्चा की और सुझाव दिया है कि **भारत को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए** और प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए EAO के साथ संचार चैनल स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

भारत-म्यांमार संबंधों का महत्व:

- **भू-राजनीतिक महत्व:**
  - **दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेशद्वार:** म्यांमार दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भूमि पुल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से इसकी निकटता एक रणनीतिक संबंध स्थापित करती है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ता है।
  - **बंगाल की खाड़ी कनेक्टिविटी:** बंगाल की खाड़ी में साझा समुद्री सीमा समुद्री सहयोग के अवसर खोलती है, जिससे आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
  - **क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:** म्यांमार के साथ मजबूत संबंध भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सकता है।
- **सामरिक महत्व:**
  - **रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोस:** म्यांमार, एक बड़ा बहुजातीय राष्ट्र, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है, जो इसके पांच पड़ोसी देशों: चीन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत को प्रभावित करता है।
  - **पड़ोसी प्रथम नीति:** भारत की "पड़ोसी प्रथम" नीति म्यांमार के साथ मजबूत, सहयोगात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के महत्व पर जोर देती है।
  - **एक्ट ईस्ट नीति:** म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
  - **बहुपक्षीय सहभागिता:** सार्क, आसियान, बिम्सटेक और मेकांग गंगा सहयोग में म्यांमार की सदस्यता द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय आयाम जोड़ती है, जो भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति के अनुरूप है।

सहयोगात्मक सहयोग के क्षेत्र:

- **द्विपक्षीय व्यापार:**
  - **व्यापार संबंध:** भारत म्यांमार का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
  - **आर्थिक अवसर:** दोनों देशों का लक्ष्य व्यापार को बढ़ाना तथा कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्रों में अवसर पैदा करना है।
- **ऊर्जा सहयोग:**
  - म्यांमार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका ऊर्जा निवेश पोर्टफोलियो 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के तेल और गैस क्षेत्र में भारत के निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनाता है।
- **बुनियादी संरचना में निवेश:**
  - **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना:** इस परियोजना का उद्देश्य भारत में कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से समुद्र के रास्ते जोड़ना, जिससे संपर्क और व्यापार में वृद्धि होगी।
  - **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:** यह राजमार्ग भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- **सामरिक रक्षा साझेदारी:**
  - **सैन्य सहयोग:** भारत और म्यांमार के बीच घनिष्ठ रक्षा साझेदारी है, वे संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और म्यांमार सेना को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
  - **भारत-म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास (IMBX):** इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य संबंधों को मजबूत करना और घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है।
- **क्षमता निर्माण उपाय:**
  - **विकासात्मक सहायता:** भारत ने म्यांमार को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण दिया है तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना सहित म्यांमार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक सहायता भी प्रदान की है।
  - **आपदा प्रतिक्रिया:** भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण और म्यांमार के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने का समर्थन करता है।
  - **मानवीय सहायता:** भारत ने कोविड-19 जैसे संकटों और चक्रवात मोरा (2017), चक्रवात कोमेन (2015) और 2010 के शान राज्य भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान की है।
- **सांस्कृतिक सम्पर्क:**
  - **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध:** साझा बौद्ध विरासत और औपनिवेशिक इतिहास राजनयिक संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करते हैं।
  - **भारतीय प्रवासी:** म्यांमार की जनसंख्या में लगभग 4% की हिस्सेदारी रखने वाले भारतीय प्रवासी, व्यवसाय, वाणिज्य और निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत-म्यांमार संबंधों में प्रमुख मुद्दे:

- **आंतरिक सुरक्षा चिंताएं:**
  - **छिद्रयुक्त सीमा:** भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा अपर्याप्त है तथा यह अविकसित, उग्रवाद-प्रवण क्षेत्र में स्थित है, जिससे आतंकवादी और विद्रोही समूहों को अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
  - **विद्रोही समूह:** विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों ने म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में शिविर स्थापित कर लिए हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।
- **मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR):** FMR से स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है और संबंध बेहतर होते हैं, लेकिन इससे अवैध आव्रजन, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के व्यापार को भी बढ़ावा मिला है।
- **त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष:** आंतरिक कलह: सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में चल रहे आंतरिक संघर्ष के कारण लगातार नागरिक अशांति बनी हुई है, जिसका कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है।
- **चीन का प्रभाव:** म्यांमार के सबसे बड़े निवेशक और व्यापारिक साझेदार चीन ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से अपना प्रभाव मजबूत कर लिया है, जिससे भारत के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है।
- **बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी:** कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और सित्तवे बंदरगाह जैसी सहयोगी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी ने आर्थिक सहयोग में बाधा उत्पन्न की है।
- **रोहिंग्या संकट:** रोहिंग्या संकट ने भारत-म्यांमार संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, तथा भारत ने अपने रुख के पीछे सुरक्षा चिंताओं और संसाधनों के बोझ को कारण बताया है।

आगे की राह

- **सामरिक कूटनीति:**
  - **मुक्त आवागमन व्यवस्था को विनियमित करना:** सीमा पार संपर्कों को संरक्षित करते हुए, बुनियादी ढांचे को उन्नत करते हुए, तथा प्रवेश बिंदुओं पर व्यापार को औपचारिक बनाते हुए, FMR का प्रभावी प्रबंधन करना।

- **अनेक हितधारकों को शामिल करना:** लोकतंत्र समर्थक हितधारकों के साथ जुड़ते हुए सैन्य सरकार के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना।
- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना।

- **सहयोगात्मक उपकरण:**
  - **दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देना:** व्यापार संबंधों में विविधता लाकर और सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की खोज करके व्यापार असंतुलन को दूर करना।
  - **बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाना:** कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना।
  - **उन्नत सुरक्षा सहयोग:** आतंकवाद रोधी उपायों, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियानों पर सहयोग करना।
- **ट्रैक II कूटनीति:**
  - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** आदान-प्रदान कार्यक्रमों, संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षिक सहयोग के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना।
  - **शांति सम्मेलन आयोजित करें:** मानवाधिकार मुद्दों पर ध्यान देने और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए क्वाड और आसियान प्रतिनिधियों के साथ शांति सभा की मेजबानी करने पर विचार करें।

निष्कर्ष:

- भारत और म्यांमार को एक दूसरे से बहुत कुछ हासिल करना है, जिससे एक पारस्परिक गतिशीलता बनती है जो उनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है। सहयोगात्मक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होकर और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध होकर, दोनों देश एक दूरदर्शी गठबंधन बना सकते हैं।

10. भारत के लिए पांच वर्षीय जलवायु एजेंडे का स्वरूप - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रसंग:

- जैसे-जैसे नई सरकार सत्ता में आएगी, उसके कुछ विकल्प इस बात में निर्णायक होंगे कि भारत किस प्रकार संधारणीय तरीके से अपनी आर्थिक राह तैयार करता है, सही मंचों पर वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में खुद को स्थापित करता है, तथा अगले पांच वर्षों में जलवायु वित्त और न्याय के लिए संघर्ष करता है।

जलवायु परिवर्तन पर भारत का परिवर्तन

- पिछले दशक में भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने वाले एक झिझकने वाले भागीदार से आगे बढ़कर आख्यानों और संस्थाओं को आकार देने वाले एक साहसिक नेता बन गया है।
- प्रथम, इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी वैश्विक संस्थाओं की नींव रखी है, साथ ही पिछले वर्ष G-20 की अपनी अध्यक्षता के तहत हरित विकास संधि को भी आकार दिया है।
- दूसरा, पहली बार भारत ने अधिक साहसिक एवं महत्वाकांक्षी उत्सर्जन शमन लक्ष्यों के बारे में बात करना शुरू किया है।
  - 2070 का शुद्ध-शून्य लक्ष्य और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) उपलब्धि हैं।
- तीसरा, भारतीय उत्सर्जन कार्बन व्यापार योजना का निर्माण, एक संस्था जो कम से कम 30-40 वर्षों तक संचालित होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण है।

अगले पांच वर्षों के लिए योजना	**उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई**
• देश जल्द ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर सकता है। • यदि इसे 2028 में संयुक्त राष्ट्र के पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी करनी हो, तो इसे G-20 की अध्यक्षता के समान ही सफल होना होगा। • 2028 में संभावित रूप से बड़ी जीत क्या हो सकती है, इस पर निर्णय लेना तथा गठबंधन बनाने और चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न देशों में इनका सामाजिकरण करना, यह कार्य अभी से शुरू किया जाना चाहिए। • इसके साथ ही, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समानता के मुद्दे पर जोर देना जारी रखना चाहिए, तथा वैश्विक संस्थाओं में अपने लिए नेतृत्व की जगह बनानी चाहिए जो जलवायु वित्त प्रदान कर सकें। • भारत को विद्युत क्षेत्र से आगे बढ़कर क्षेत्रीय उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को अपनाना होगा तथा उन्हें दृढ़तापूर्वक संप्रेषित करना होगा। • भारत ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और वह अपने अंतर्राष्ट्रीय गैर-जीवाश्म शेयर-संबंधी तथा घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए ऐसा करना जारी रखेगा। • अगला कदम लक्ष्य को अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करना है। उदाहरण के लिए, यह निजी परिवहन क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, जिससे शून्य-कार्बन दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य दिया जा सके।	• अंत में, गहराई से देखने पर यह पता चलता है कि सरकार के इस कार्यकाल में उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई और लचीलापन सामने आना चाहिए। • सरकार को केंद्र-राज्य समन्वय समूह बनाने तथा सोलहवें वित्त आयोग के माध्यम से राज्य स्तरीय जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना चाहिए। • भारत के संघीय ढांचे को देखते हुए, इस सिफारिश का मतलब जलवायु संबंधी कार्यों को केंद्रीकृत करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि राज्य स्तरीय कार्यों का उनकी स्वायत्तता से समझौता किए बिना बेहतर समन्वय हो। • नई सरकार को अपने नए कार्यकाल में भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व को अगले स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

GEO IAS
It's about quality

फैक्ट फटाफट

1. भारत में घड़ियाल की आबादी - द हिन्दू

प्रसंग:

- हाल ही में पूर्वी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में एक अकेली मादा घड़ियाल ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसने अस्थायी रूप से एक सींग वाले गैंडे को पीछे छोड़ दिया है। वन्यजीव अधिकारी और विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि यह घड़ियाल पार्क के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी खंड में कैसे पहुँच गया। हालाँकि, वे इस बात से सहमत हैं कि यह लगभग वयस्क सरीसृप नदी में घड़ियाल की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

घड़ियाल प्रजाति :

- घड़ियाल, जिन्हें गेवियल के नाम से भी जाना जाता है, एशियाई मगरमच्छों की एक विशिष्ट प्रजाति है, जिन्हें उनकी लम्बी, संकरी थूथन से आसानी से पहचाना जा सकता है।
- मगरमच्छ परिवार में मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं।
- भारत तीन मगरमच्छ प्रजातियों का घर है:
  - **घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस):** IUCNरेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध।
  - **मगर क्रोकोडाइलस (क्रोकोडाइलस पैलस्ट्रिस):** IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत।
  - **साल्टवाटर क्रोकोडाइलस** (क्रोकोडाइलस पोरोसस): IUCN द्वारा कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया।
- तीनों प्रजातियाँ CITES के परिशिष्ट-I और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी को छोड़कर, जिन्हें CITES के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है।

घड़ियालों का निवास स्थान:

- **प्राकृतिक आवास:** उत्तरी भारत के मीठे जल में पाया जाता है।
- **प्राथमिक आवास:** चम्बल नदी (यमुना की एक सहायक नदी)।
- **द्वितीयक आवास:** घाघरा, गंडक, गिरवा नदियाँ (उत्तर प्रदेश), रामगंगा नदी (उत्तराखंड), और सोन नदी (बिहार)।

महत्व:

- घड़ियालों की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

संरक्षण के प्रयासों:

- **प्रजनन केंद्र:** लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल इको पार्क, मध्य प्रदेश)।

चेतावनी:

- नदी प्रदूषण में वृद्धि
- बांधों का निर्माण
- बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य
- पानी की बाढ़
- अवैध रेत खनन
- अवैध शिकार
- अतिरिक्त जानकारी:
- घड़ियाल का आहार मुख्य रूप से मछली है, और उनकी उपस्थिति नदियों में स्वस्थ मछली आबादी का संकेत देती है।
- संरक्षण कार्यक्रम दशकों से चलाए जा रहे हैं, फिर भी इस प्रजाति को मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- घड़ियालों के सफल संरक्षण के लिए जन जागरूकता और भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- काजीरंगा में एकमात्र मादा घड़ियाल की खोज से भारत में घड़ियाल संरक्षण के लिए नई अंतर्दृष्टि और रणनीतियां सामने आ सकती हैं।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

2. रेडिएशन बायोडोसिमेट्री – द हिंदू

प्रसंग

- बड़े पैमाने पर रेडियोलॉजिकल घटना के बाद, जैसे कि इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर डिवाइस या रिएक्टर दुर्घटना, उन व्यक्तियों की तुरंत पहचान करना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हाल ही में स्वीकृत विकिरण बीमारी दवाओं को समय पर प्रशासित करने के लिए महत्वपूर्ण विकिरण खुराक प्राप्त की है। शीघ्र मूल्यांकन उन लोगों को आश्वस्त करने में भी मदद करता है जो महत्वपूर्ण रूप से जोखिम में नहीं हैं, जिससे अस्पताल में भीड़भाड़ को रोका जा सकता है।

बायोडोसिमेट्री क्या है?

- बायोडोसिमेट्री रक्त, मूत्र या बालों में परिवर्तन का विश्लेषण करके विकिरण जोखिम के स्तर को निर्धारित करती है, जो विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत विकिरण निगरानी उपकरण नहीं होते हैं।

मुख्य बिंदु

- **डिसेंट्रिक क्रोमोसोम परख (DCA)**
  - **क्रियाविधि:** श्वेत रक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र विपथन को मापता है, विशेष रूप से द्विकेंद्री गुणसूत्रों (DC) को, जो विकिरण के कारण विशिष्ट रूप से बनते हैं।
  - **प्रक्रिया:** लिम्फोसाइटों का संवर्धन किया जाता है, गुणसूत्रों को फैलाया और रंगा जाता है, तथा DC की गणना की जाती है।
  - **समय सीमा:** परिणाम के लिए 2-3 दिन।
  - **उपयोग:** छोटे पैमाने की विकिरण दुर्घटनाओं के लिए प्रभावी; बड़े पैमाने की घटनाओं में सीमित प्रवाह।
- **साइटोकाइनेसिस ब्लॉक माइक्रोन्यूक्लियस परख (CBMN)**
  - **क्रियाविधि:** विभाजित श्वेत रक्त कोशिकाओं में सूक्ष्मकणिकाओं के निर्माण का पता लगाता है, जो विकिरण जोखिम का संकेत है।
  - **प्रक्रिया:** कोशिकाएं विभाजित होती हैं, लेकिन पूर्ण विभाजन से पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है, जिससे द्विकेन्द्रकीय कोशिकाएं बन जाती हैं।
  - **समय सीमा:** लंबे समय तक संवर्धन के कारण लगभग 3 दिन।
- **गामा-H2AX परख**
  - **क्रियाविधि:** फॉस्फोरिलेटेड गामा-H2AX हिस्टोन प्रोटीन के स्तर को मापता है, ताकि उजागर को अप्रकाशित से अलग किया जा सके और विकिरण खुराक के स्तर का निर्धारण किया जा सके।
  - **प्रक्रिया:** कोशिका संवर्धन की आवश्यकता नहीं; परिणाम 6-8 घंटे के भीतर मिल जाते हैं।
  - **समय सीमा:** हिस्टोन फॉस्फोरिलीकरण गतिकी के कारण 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।

3. स्वामी विवेकानंद – पीआईबी

प्रसंग:

- स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी विरासत को सम्मानित किया तथा एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज के उनके सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

योगदान:

- वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को विश्व मंच पर पेश किया।
- उन्होंने 'नव-वेदांत' की वकालत की, हिंदू धर्म की व्याख्या पश्चिमी परिप्रेक्ष्य से की तथा भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिकता के मिश्रण पर जोर दिया।
- भारत के पुनरोद्धार के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया तथा 'मानव-निर्माण' और 'चरित्र-निर्माण' वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए उन्हें वैश्विक मान्यता मिली।
- उन्होंने अपनी पुस्तकों में मोक्ष (सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति) प्राप्त करने के लिए चार मार्ग बताए हैं: राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा "आधुनिक भारत के निर्माता" के रूप में प्रशंसा की गई।

- **दार्शनिक प्रभाव:** स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का भारतीय और पश्चिमी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, तथा उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को आत्म-साक्षात्कार और समाज सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है।
- **साहित्यिक योगदान:** उनके लेखन और भाषणों का अध्ययन उनकी गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए जारी है।
- **विरासत:** स्वामी विवेकानंद की विरासत रामकृष्ण मिशन के चल रहे कार्यों के माध्यम से कायम है, जो एक सामंजस्यपूर्ण, शिक्षित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के उनके दृष्टिकोण को कायम रखता है।

संबद्ध संगठन:

- 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य।
- 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका ध्यान मूल्य आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण तथा आपदा राहत और पुनर्वास पर केंद्रित था।
- 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है।

मान्यता:

- उनकी जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, उन गतिविधियों के साथ मनाई जाती है जो युवाओं को साहस, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के उनके आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती हैं।
- अपनी शिक्षाओं और आदर्शों की पुनर्व्याख्या करके, स्वामी विवेकानंद ने भारत में आधुनिक आध्यात्मिक विचार और शिक्षा की नींव रखी और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रही है।

GEO IAS
It's about quality

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. निम्नलिखित कथन पर विचार करें

कथन I: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एक सीमांकन रेखा है जो पश्चिमी हिमालय में भारत-नियंत्रित क्षेत्र लद्दाख और चीन-नियंत्रित क्षेत्र अक्साई चिन को अलग करती है।

कथन II: यह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या नहीं है
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q2. आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. आयुष्मान भारत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य कमजोर परिवारों को उच्च चिकित्सा लागत के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) आयुष्मान भारत का प्रमुख घटक है, जो सेवा केंद्र पर लाभार्थी को नकदी रहित और कागज रहित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
3. आयुष्मान भारत में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWC) की स्थापना भी शामिल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q3. हरित हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. इसका उत्पादन पवन, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है।
2. कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण, या प्राकृतिक गैस या मीथेन के भाप मीथेन सुधार द्वारा उत्पादित।
3. जीवाश्म ईंधन को जलाकर उत्पन्न बिजली का उपयोग करके उत्पादित, लेकिन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) या कार्बन कैप्चर उपयोग (CCU) प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ा गया

निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q4. कार्बन मूल्य निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक ऐसा उपकरण है जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की बाहरी लागतों को पकड़ता है और मूल्य निर्धारण के माध्यम से उन्हें उनके स्रोतों से जोड़ता है।
2. यह आमतौर पर उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) पर कीमत के रूप में होता है
3. इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान का बोझ उन लोगों पर डालने में मदद मिलती है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3.

Q5. माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये कपड़ों और वस्त्रों से निकलने वाले माइक्रोफ़ाइबर होते हैं
2. द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स सूर्य की विकिरण के संपर्क में आने से बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं।
3. माइक्रोप्लास्टिक विभिन्न रसायनों, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया और रोगजनकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q6. निम्नलिखित में से कौन से देश QUAD समूह का हिस्सा हैं?

1. जापान
2. ब्रिटेन
3. अमेरिका
4. फ्रांस
5. भारत
6. ऑस्ट्रेलिया

सही उत्तर कूट का चयन करें:

A. 1, 2, 4, 6
B. 1, 3, 5, 6
C. 2, 3, 4, 5
D. 1, 2, 5, 6

Q7. भारतीय राजनीतिक प्रणाली की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति इसकी संघीय भावना को प्रतिबिंबित करती है?

1. राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद
2. नये राज्यों के निर्माण की मांग
3. राज्यों द्वारा अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय अनुदान की मांग
4. क्षेत्रीय दलों का उदय और राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान
5. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रति राज्य का विरोध

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

A. केवल 1, 2 और 3
B. केवल 2, 4 और 5
C. केवल 3, 4 और 5
D. 1, 2, 3, 4 और 5

Q8. उत्पादक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर उत्पादक द्वारा प्राप्त औसत मूल्य परिवर्तन को मापता है।
2. यह सेवाओं में मूल्य परिवर्तन को प्रतिबिंबित नहीं करता है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

Q9. निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय समूह में भारत और म्यांमार दोनों सदस्य हैं?

1. आसियान
2. बिम्सटेक
3. सार्क
4. मेकांग गंगा सहयोग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 2 और 3
B. केवल 1 और 4
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1 और 2

Q10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के नेतृत्व वाली पहल परिवहन क्षेत्र सहित सतत जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और सहयोग को सुगम बनाने के लिए।
2. भारत, ब्राजील और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य हैं
3. यह भारत के पीएम-जीवन योजना, सतत जैसे कार्यक्रमों को गति देने में भी मदद करेगा।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प C सही है

व्याख्या

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एक सीमांकन रेखा है जो पश्चिमी हिमालय में भारत-नियंत्रित क्षेत्र लद्दाख और चीन-नियंत्रित क्षेत्र अक्साई चिन को अलग करती है।
- मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है।

उत्तर : 2 विकल्प C सही है

व्याख्या

- आयुष्मान भारत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य उच्च चिकित्सा लागतों के विरुद्ध कमज़ोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। **इसलिए, कथन 1 सही है**
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) वास्तव में आयुष्मान भारत का प्रमुख घटक है। यह लाभार्थी को सेवा के स्थान पर सेवाओं तक नकद रहित और कागज रहित पहुंच प्रदान करता है, तथा अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करता है। **इसलिए, कथन 2 सही है**
- आयुष्मान भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए अपने व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWC) की स्थापना शामिल है। इन केंद्रों का उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक देखभाल सहित कई सेवाएँ प्रदान करना है। **इसलिए, कथन 3 सही है**।

उत्तर : 3 विकल्प A सही है

व्याख्या

- हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पवन, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता
- ग्रे हाइड्रोजन- कोयले या लिग्नाइट गैसीकरण के माध्यम से या प्राकृतिक गैस या मीथेन के भाप मीथेन सुधार द्वारा उत्पादित। ये प्रक्रियाएँ आमतौर पर कार्बन-गहन होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस जलने पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है।
- ब्लू हाइड्रोजन - जीवाश्म ईंधन को जलाकर उत्पन्न बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, लेकिन ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) या कार्बन कैप्चर उपयोग (CCU) प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ा जाता है

उत्तर : 4 विकल्प C सही है

व्याख्या

- यह एक ऐसा उपकरण है जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की बाहरी लागतों को पकड़ता है और उन्हें मूल्य के माध्यम से उनके स्रोतों से जोड़ता है **(इस प्रकार कथन 1 सही है)**
- यह आमतौर पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) पर कीमत के रूप में होता है **(अतः कथन 2 गलत है)**
- इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान का बोझ उन लोगों पर डालने में मदद मिलती है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। **(इस प्रकार कथन 3 सही है)**

उत्तर : 5 विकल्प C सही है

व्याख्या

- प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स छोटे कण होते हैं जिन्हें वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है तथा ये कपड़े और वस्त्रों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, प्लास्टिक छर्रों और प्लास्टिक फाइबर में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स।
- द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स का निर्माण बड़े प्लास्टिक, जैसे पानी की बोतलों के टूटने से होता है, जो सूर्य की विकिरण और समुद्री लहरों जैसे पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने के कारण होता है।
- माइक्रोप्लास्टिक विभिन्न रसायनों, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया और रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, तथा यदि वे जल उपचार प्रक्रिया से बच जाते हैं, तो जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं।

उत्तर : 6 विकल्प B सही है

व्याख्या

- क्वाड सुरक्षा वार्ता (क्वाड) एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो शिखर सम्मेलनों, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यासों के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को एक साथ लाता है।

- 2007 में इस मंच की शुरुआत एक संवाद के रूप में हुई।
- इस कूटनीतिक और सैन्य समझौते को मोटे तौर पर चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया।

उत्तर : 7 विकल्प D सही है

व्याख्या

- यद्यपि भारत के संविधान ने एक मजबूत केन्द्रीय सरकार का निर्माण किया है, लेकिन इसने **राज्य सरकारों को कमजोर नहीं बनाया है** और न ही उन्हें केन्द्रीय सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एजेंसियों के स्तर तक कम किया है।
- भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक **नए प्रकार का संघ** ' बताया गया है।
- राज्य **सरकारें स्वायत्त इकाइयाँ** हैं **जो समान लक्ष्यों को प्राप्त करने** के लिए केंद्र के साथ मिलकर संवैधानिक **ढांचे के तहत** काम करती हैं।

उत्तर : 8 विकल्प D सही है

व्याख्या

- यह बाजार में पहुंचने से पहले उत्पादन के स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में होने वाला औसत परिवर्तन है।
- यह उत्पादक को प्राप्त होने वाली औसत कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।
- PPI अनुमान में अप्रत्यक्ष कर, परिवहन और वितरण लागत शामिल नहीं हैं।
- PPP का महत्व
- PPP का उपयोग मुद्रास्फीति और अपस्फीति के माप के रूप में किया जाता है।
- PPP का उद्देश्य प्रमुख इनपुट की कीमतों के आधार पर निजी अनुबंधों में एस्केलेटर क्लॉज की गणना करना है।
- एस्केलेटर क्लॉज एक अनुबंध प्रावधान है जो अनुबंध के प्रभावी रहने के दौरान कुछ शर्तों में परिवर्तन होने पर सहमत वेतन या कीमतों में स्वतः वृद्धि की अनुमति देता है।
- यह इनपुट और आउटपुट लागत की तुलना के रूप में कार्य करता है।

उत्तर : 9 विकल्प C सही है.

आसियान

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना एशिया-प्रशांत के उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- आसियान सचिवालय – इंडोनेशिया, जकार्ता।
- सदस्य राष्ट्र: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इसलिए यह बात गलत है क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है।

बिम्सटेक

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है।
- इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक सुसंगत क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
- सदस्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। **अतः बिंदु 2 सही है।**

उत्तर : 10 विकल्प C सही है

व्याख्या :

- जैव ईंधन को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग के बीच गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व में पहल।
- उद्देश्य: परिवहन क्षेत्र सहित सतत जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
- संस्थापक सदस्य: भारत, ब्राजील और अमेरिका
- यह भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे कि पीएम-जीवन योजना, सतत को गति देने में भी मदद करेगा। इसलिए सभी कथन सही हैं।

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com